इक्विपमेंट्स का कहना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 25 करोड़ से ज्यादा की मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने पर तीन साल तक 15 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। इससे नोएडा

अंसोसिएशन के प्रेजिडेंट दिनेश जैन कहते हैं कि यह मीडियम इंडस्ट्री के लिए बेहतर प्लान है। सरकार की मंशा व घोषणा अच्छी है।

तैयार किए जा सकते हैं। इन इंडस्ट्री में तैयार प्रॉडक्ट्स से मार्केट में कॉम्पिटिशन हो सकती है।

रियल एस्टेट को FDI की संजीवनी

20

हजार वर्ग मीटर के प्रोजेक्ट पर हो सकेगा विदेशी पूंजी निवेश

■ **विशेष संवाददाता, नोएडा :** मोदी सरकार के पहले बजट ने रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदों को भारी राहत दी है। इसमें अब एफडीआई के दरवाजे खोलने से विदेशी कंपनियों के निवेश का रास्ता खुल गया है। नोएडा में बड़ी तादाद में रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्डिंग क्षेत्र में काम कर रही हैं। बजट में देश में 100 स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा ने भी रियल एस्टेट के चेहरे पर रौनक ला दी है।

एक रियल एस्टेट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शक्तिनाथ कहते हैं कि अभी तक 50 हजार वर्ग मीटर तक के प्रोजेक्ट पर एफडीआई का प्रावधान था। इसे घटाकर 20 हजार वर्ग मीटर तक कर दिया गया है। इससे 20 हजार वर्ग मीटर के प्रोजेक्ट्स में भी एफडीआई हो सकेगा। इसके अलावा पहले 10 मिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी। इसे भी घटाकर पांच मिलियन यूएस डॉलर कर दिया गया है। इससे छोटे इन्वेस्टर भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पैसा लगा सकेंगे। उन्होंने बताया कि आम बजट में अफोर्डेबल होम बनाने के लिए प्रोत्साहन नीति बनाई गई है। अभी तक हाउसिंग लोन पर लगने वाले ब्याज में डेढ़ लाख तक की छूट की सीमा बढ़ाकर दो लाख करने से ज्यादा से ज्यादा लोग होम लोन लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ हुआ तो इसका भी पॉजिटिव असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। यही नहीं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन करने के बाद छोटे इन्वेस्टर भी अपनी प्रॉपर्टी को लिस्टिंग करा सकेंगे।

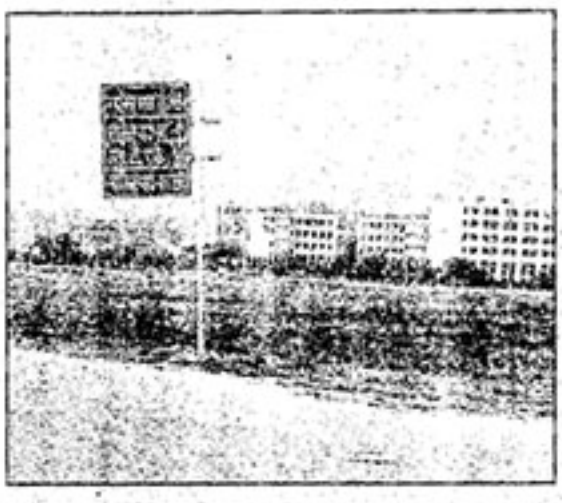

IIT खुलने का मौका चूक गया शहर

500

करोड़ रुपये का प्रावधान 5 आईआईटी और 5 आईआईएम के लिए, पर कोई ग्रेटर नोएडा के लिए नहीं

■ **वस, ग्रेटर नोएडा :** शिक्षाविद इस बार के बजट को प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस बता रहे हैं हालांकि बजट में पांच आईआईटी और पांच आईआईएम का प्रावधान तो हुआ, लेकिन इनमें से कोई ग्रेटर नोएडा में नहीं खुलेगा। इससे यहां के स्टूडेंट्स में निराशा है। 5 आईआईटी और 5 आईआईएम के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। ग्रेटर नोएडा की पहचान चूंकि एजुकेशनल हब के रूप में है, लिहाजा उम्मीद थी कि बजट में यहां के लिए भी कुछ तोहफे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

प्राइमरी स्कूल की टीचर सुमन लता पटेल का कहना है कि प्राइमरी व सर्व शिक्षा अभियान के लिए 56 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी काफी नहीं है। शिक्षा के लिए और भी प्रावधान की जरूरत थी। विकसित देशों में जीडीपी का 5 प्रतिशत शिक्षा के लिए रहता है जबकि भारत में करीब 2.5 प्रतिशत ही है।

किसानों को बिचौलियों से निजात नहीं

■ **वस, ग्रेटर नोएडा :** जिले कि किसानों ने बजट को निराश करने वाला बताया है। किसान कह रहे हैं कि बजट को पूंजिपतियों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक बिचौलियों का रोल कम करने का काम भी नहीं किया है। डीजल पर सब्सिडी नहीं दी और यूरिया के लिए नई नीति बनाने की बात है, जो किसानों की फसलों की लागत को बढ़ा देगी।

100

करोड़ पूर्वोत्तर राज्यों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, पर डीजल पर सब्सिडी नहीं

बजट में सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। किसान नेता डॉ. रूपेश वर्मा की मानें तो किसानों को उम्मीद थी कि डीजल पर सब्सिडी बढ़ेगी, लेकिन इसे कम करने की बात की गई है।

Design : Amit Dhingra
Illustration : Manish Verma